समाचार अवलोकन

मौसम का मिजाज, बिन बारिश बाढ़

अमर उजाला : अप्रैल 3, 2007

हिमालय की ऊंची चोटियों पर इस बार हुई भारी बर्फबारी से गर्मियों में हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के जलस्तर में वद्धि की आशंका जाहिर की गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान जैसे ही 40 डिग्री से ऊपर जाएगा, बर्फ पिघलने की रफ्तार तेज हो जाएगी। यदि मानसूनी बारिश अच्छी हो गई तो बाढ़ के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। मौसम विभाग इसरो के उपग्रहों की मदद से ग्लेशियरों के पिघलने और नदियों के जलस्तर पर अभी से पैनी निगाह रखे हुए है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार मार्च के मध्य में भारी बर्फबारी होने से हिमालय के ग्लेशियरों में 11 से 15 फीट तक बर्फ जमी, लेकिन इससे तेजी से पिघल रहे ग्लेशियरों को खास लाभ नहीं हो रहा है। जाने माने ग्लेशियर वैज्ञानिक प्रोफेसर इकबाल हुसनैन के अनुसार देर से गिरी बर्फ को क्रिस्टल स्वरूप धारण करने के लिए जरूरी समय ही नहीं मिल पाया है। इसके लिए कम से कम तीन महीने का कम तापमान का अंतराल चाहिए तभी वह क्रिस्टल में परिवर्तित होती है और ग्लेशियरों का आकार बढ़ाती है, लेकिन बर्फबारी होने के बाद से ही तापमान बढ़ना शुरू हो गया था और बर्फ धीरे–धीरे पिघलनी शुरू हो गई। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र के वैज्ञानिक डा० के०के० सिंह के अनुसार बर्फ पिघलने से बाढ़ के हालात भले ही नहीं हों, लेकिन इतना तय है कि इस बार हिमालयी नदियों में पानी खूब रहेगा भले ही बारिश कम ही क्यों न हो।

उत्तराखण्ड ग्रेटअर्थक्वेक के मुहाने पर

दैनिक जागरण : अप्रैल 5, 2007

उत्तराखण्ड राज्य ग्रेटअर्थक्वेक यानी आठ से अधिक मैग्नीट्यूड के बड़े भूकंप के मुहाने पर है। यहां पिछली एक–दो शताब्दियों में बड़े भूकंप नहीं आए हैं। तथा इस क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक बड़े थ्रस्ट व फाल्ट स्थित हैं साथ ही भारतीय भूगर्भीय प्लेट के एशियाई प्लेट में धंसने से धरती के गर्भ में बड़ी मात्रा में ऊर्जा एकत्रित हो रही है। यह ऊर्जा बड़े भूकंप के रूप में कभी भी बाहर आकर भू–पटल पर तांडव मचा सकती है। डीएसटी भी इसी कारण राज्य को सर्वाधिक महत्व दे रहा है। नैनीताल स्थित भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय–डीएसटी की परियोजना 'सेस्मिक नेटवर्क इन कुमाऊं हिमालया' के मुख्य परामर्शदाता प्रो० चारू पंत ने निकट भविष्य में 'ग्रेटअर्थक्वेक' की आशंका जताते हुए कहा कि राज्य में पिछली एक–दो शताब्दियों में बड़े भूकंपों का न आना यहां गंभीर खतरे के संकेत हैं। इस कारण राज्य को भूकंप के लिहाज से सर्वाधिक संवेदनशील मानते हुए 'लाक्ड पोर्सन' इंगित कर दिया गया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में नैनीताल से गुजरने वाला मेन बाउंड्री थ्रस्ट–एमबीडी, चमोली–मुनस्यारी–धारचूला से गुजरने वाले मेन सेंट्रल थ्रस्ट, नार्थ अल्मोड़ा थ्रस्ट, रामगढ़ थ्रस्ट व बेरीनाग थ्रस्ट जैसे कई बड़े भूगर्भीय थ्रस्ट व फाल्ट मौजूद हैं। इसके अलावा लद्दाख से ब्रह्मपुत्र नदी के साथ–साथ मानसरोवर से गुजरते हुए आसाम तक भारतीय भू–प्लेट एशियाई प्लेट के

भीतर प्रतिवर्ष छः से आठ सेमी की दर से समा रही है। इन कारणों से कई स्थानों पर धरती का 11 मिमी प्रतिवर्ष की दर से ऊपर उठना भी रिकार्ड किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूगर्भ में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा एकत्र हो रही है, जो कभी भी भूकंप के रूप में भू–पटल पर तबाही मचा सकती है।

कहीं मिट न जाए गांवों का अस्तित्व

अमर उजाला : अप्रैल 19, 2007

टिहरी बांध के जलाशय से लगी ढलानों के दरकने से आसपास के दस से अधिक गांवों को खतरा पैदा हो गया हैं। भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण (जीएसआई) के सर्वे में इस बात का खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट से महत्वाकांक्षी टिहरी बांध परियोजना पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। रिपोर्ट में ढलानों पर बसे दस गांवों में सुरक्षा उपाय करने की सिफारिश की गई है। सर्वे के अनुसार इन ढलानों में आई दरारों के कारण भागीरथी घाटी के बरोला, कंसाली, रौलाकोट, नकोट, तल्लाउप्पु, भाल्ड, बधान और हदियारी गांवों पर गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। यह सर्वे भागीरथी के दाहिने और भिलंगना नदी के बाएं किनारे पर किया गया है। सर्वे में सोड उप्पु, बालडोगी और मुंद्रा सेरा की निचली ढलानों को भी असुरक्षित बताया गया है। टिहरी बांध परियोजना ने सर्वे की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है। 29 मार्च 2007 को हुए इस सर्वे की रिपोर्ट के बाद जीएसआई के निदेशक पी०सी० नवानी ने कहा है कि जलाशय की परिधि पर पानी के प्रभाव का असर जानने के लिए झील को 830 मीटर तक भरना होगा। इसके लिए उन्होंने सूक्ष्म मानीटरिंग की सिफारिश की है।

संकट : गोमुख का आकार घटा

दैनिक जागरण : मई 22, 2007

गंगोत्री–गोमुख क्षेत्र में बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ ही मानवीय आवाजाही तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह गतिविधियों के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों पर संकट मडराने लगा है। इससे जहां नदियों का जल स्तर दिनोंदिन घट रहा है, वहीं संरक्षित सूची में शामिल जीव व वनस्पतियों के लुप्त होने की कगार पर आने से पर्यावरण असंतुलन का खतरा विकराल रूप लेने लगा है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगोत्री–गोमुख क्षेत्र का आकार घटता जा रहा है। यदि समय रहते इस ओर नियंत्रण व संरक्षण को लेकर सटीक नीति न बनी तो वह दिन दूर नहीं जब ग्लेशियरों का अस्तित्व समाप्त होने के बाद देशभर में पानी के लिए त्राहि–त्राहि मच जाएगी। ऐसे में गंगा के उद्गम स्थल गोमुख क्षेत्र की ओर पर्यटकों व पर्वतारोहियों द्वारा फैलाए जा रहे जैविक व अजैविक कूड़े करकट से भी ग्लेशियरों के साथ पर्यावरण को संतुलित बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले दुर्लभ श्रेणी में शामिल बरड़, कस्तूरा, मौनाल, स्नो लैपर्ड, हिरन जैसे जीव–जंतुओं पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। जबकि पवित्र भोजपत्र कैल, देवदार, थुनेर प्रजाति के वक्ष भी पर्यावरणीय प्रदूषण की चपेट में आने से विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। बहरहाल गंगोत्री–गोमुख क्षेत्र में सैरगाह के नाम पर पर्यटकों की

बढ़ती आवाजाही से धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है। साथ ही पर्यावरण के विपरीत चल रही गतिविधियों से ग्लेशियरों पर संकट मडराना भी स्वाभाविक है। ऐसे में लगभग 28 किमी० आकार के गोमुख का मात्र 26 किमी० रहने तथा शेष हिस्से के तेजी से पिघलने पर पेयजल संकट के गहराने से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

विदेश में फैलेगी प्रदेश के फूलों की खुशबू

अमर उजाला : जून 7, 2007

प्रदेश से फूलों के निर्यात बढ़ने की संभावना बलवती हुई है। प्रदेश सरकार की ओर से विश्व की सबसे बड़ी फूलों की मंडी (हालैंड) में भेजे गए सैंपल स्वीकार कर लिए गए हैं। इससे प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खास बात यह है कि यह सैंपल ग्लेडुलस के हैं, जिनकी उपज इस राज्य में सबसे अधिक हो रही है। फूलों के निर्यात में प्रदेश को पिछले दो सालों में खास सफलता नहीं मिली। वर्ष 2004–2005 में 3.4 मीट्रिक टन और 3.59 लाख रूपये मूल्य का निर्यात हुआ था। वर्ष 2005–2006 में तो कुल 1.18 मीट्रिक टन और 2.1 लाख रूपये मूल्य का ही निर्यात किया जा सका। इस वर्ष यह तस्वीर बदलने की उम्मीद की जा रही है। इस समय करीब 525 हेक्टेयर में 558 मीट्रिक टन फूल उगाए जा रहे हैं और क्षेत्रफल के हिसाब से इसमें से करीब 80 प्रतिशत हिस्सेदारी ग्लेडुलस और मैरीगोल्ड की है। उत्पादन में भी इन दो किस्सों के फूलों का हिस्सा करीब 82 प्रतिशत है। शासन से मिली जानकारी के मुताबिक अब विश्व की मंडी में फूलों के बेहतर दाम मिलने की संभावना रहेगी।

उत्तर भारत में आठ भूकंपीय फाल्ट

अमर उजाला : जून 20, 2007

इस समय पूरे उत्तर भारत को भूंकपीय दष्टि से 8 फाल्ट्स से खतरा है। ये सभी फाल्ट हिमालय, खासकर उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से होकर निकल रहे हैं। आई०आई०टी०, रूड़की इंस्टीट्यूट की ओर से जारी सिस्मिक हेजार्ड इन द नार्दन इंडिया रीजन नामक रिपोर्ट में इनके विषय में भी बताया गया है, जहां पर भूकंप आने की दशा में पथ्वी की सतह हिलने वाली है। उत्तर भारत के भूकंपीय क्षेत्र के संदर्भ में किए गए अध्ययन की ताजा रिपोर्ट में इस बात को दर्शाया गया है कि आने वाले समय में किन किन स्थानों पर पथ्वी की सतह हिलेगी। इनमें उत्तर भारत के दो दर्जन से अधिक स्थान हैं। इनमें दिल्ली तथा उत्तराखण्ड में नैनीताल हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी, धारचूला तथा पिथौरागढ़; उ०प्र० में बिजनौर, बरेली, बुलंदशहर, सहारनपुर; हरियाणा में अंबाला, रेवाड़ी तथा रोहतक; चण्डीगढ़ के अलावा हिमाचल प्रदश के चंबा, मनाली, मंडी, शिमला प्रमुख स्थान हैं। पिछले लम्बे समय से हिमालयन रीजन की भूकंपीय स्थिति का सबसे सटीक अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ रोजर बिल्हम हैं। उनके शोध हिमालयन सिस्मिक हेजार्ड सी साइंसेज 2001 नामक रिपोर्ट से जो निष्कर्ष निकले हैं, उनके अनुसार प्रत्येक 100 से 300 वर्ष के बीच 8 या उससे भी बड़े मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है। यह बड़ी

तबाही लाने के लिए काफी होता है। इसका समय अब आ गया है। हालांकि भूकम्प के अध्ययन में अभी तक भविष्यवाणी किए जाने जैसी खोज नहीं की गई है, लेकिन प्रो० बिल्हन ने 24 अगस्त 2001 को जारी अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया था कि उत्तर भारत के क्षेत्र में आठ या उससे भी अधिक तीव्रता वाला भूकंप आने वाला है। उन्होने अपने शोध में बताया कि 1905 में आए कांगड़ा भूकंप के बाद से हिमालयन क्षेत्र में इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी हो गई है कि उससे करीब १० मैग्नीट्यूड का भूकंप आ सकता है।

सपना हो जायेगी भंगीरे की चटनी व कुणी की खीर

दैनिक जागरण : जून 27, 2007

परम्परागत फसलों की उपेक्षा अब पहाड़ के लोगों को मंहगी पड़ने वाली है। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली चार महत्वपूर्ण फसलें खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी हैं। प्रदेश सरकार ने इन्हें लुप्त हो रही फसलों की श्रेणी में शामिल कर लिया है, लेकिन इन्हें बचाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हो पायी है। उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रो में कई फसलें अनूठी हैं। देश के कई हिस्सों में इन फसलों का उत्पादन नहीं होता। परम्परागत ढंग से उगाई जाने वाली ये फसलें पौष्टिक होने के साथ ही साथ औषधीय महत्व की भी हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से पर्वतीय क्षेत्र की फसलें उपेक्षा का शिकार हैं। कषि विभाग ने इस ओर कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी जिलों को संकटग्रस्त फसलों के सर्वेक्षण के निर्देश दिये। पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में हुए सर्वेक्षण में यह बात सामने आई कि चार महत्वपूर्ण फसलें काकूण (कुणी), लाल राजमा, भगिंरा और फाफर खत्म होने के कगार पर है। इनमें कुणी खरीफ की फसल है। इसमें चावल की तरह गोल दाने निकलते है। कुणी की खीर पर्वतीय क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय रही है। इसी तरह लाल राजमा आठ दस हजार फिट से अधिक की ऊंचाई पर पैदा होती है। सामान्य राजमा से छोटे आकार की लाल राजमा बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट है, इसी ऊंचाई पर पैदा होता है फाफर। धार्मिक दष्टि से पवित्र माने जाने वाला फाफर का आटा तीज प्यौहारों में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन किसानों ने अब इसकी जगह व्यावसायिक फसलों को अधिक तवज्जो देना 'ुरू कर दिया है। पहाड़ी भांग की चटनी मैदानों में भी लोकप्रिय है। भंगिरा से बनने वाली चटनी का स्वाद शायद निकट भविष्य में लोग नहीं ले पायेंगे क्योंकि यह भी संकटग्रस्त फसलों की श्रेणी में शामिल हो गयी है। प्रदेश के कषि मकहमे द्वारा किये गये एक सर्वे के बाद इन्हें संकटग्रस्त फसलों की श्रेणी में शामिल किया गया है। संकटग्रस्त घोषित होने के बाद भी इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए फिलहाल कोई पहल नहीं हो रही है।

हिमालयी क्षेत्र के लिए विकास नीति जरूरी

दैनिक जागरण : जुलाई 8, 2007

गोविन्द बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, कोसी–कटारमल में हिमालयी क्षेत्र के 'बायोस्फेयर रिजर्व क्षेत्रें के बेहतर प्रबंधन' पर हुई दो दिनी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि, केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव बी०एस० परसीरा ने

कहा कि हिमालयी क्षेत्र सबसे अधिक संवेदनशील होने के नाते इस क्षेत्र में स्थित 10 जैवमंडलों के वैश्विक बदलाव एवं मानव गतिविधियों के मद्देनजर विकास नीति बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हिमालयी बायोस्फेयर रिजर्व जल प्रवाह व ईको टूरिज्म की दष्टि से भी अद्वितीय है। तथा जैव व मानव केंद्रित प्रयासों के गठजोड़ से जैवमंडल क्षेत्रें के लिए स्थायी विकास का माडल तैयार करना है। इस मौके पर उन्होंने संस्थान एवं वन विभाग सिक्किम एवं आसाम द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कंचनजंगा एवं पनास बायोस्फेयर रिजर्व को यूनेस्को के मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम में शामिल करने हेतु विभिन्न रिपोर्टों का भी विमोचन किया।

ग्लेशियरों के पिघलने की गति चिंताजनक नहीं

दैनिक जागरण : अगस्त 23, 2007

ग्लेशियर पिघलना एक सामान्य प्रक्रिया है। भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के उप महानिदेशक और हिम विज्ञानी डा० दीपक श्रीवास्तव का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने की गति किसी भी स्थिति में चिंताजनक नहीं है। करोड़ों सालों से ग्लेशियरों का बनना और पिघलना जारी है। उन्होंने कहा कि सदैव से पिघलते आ रहे ग्लेशियरों के कारण ही गंगा एवं अन्य नदियों में पानी आ रहा है। ग्लेशियर यदि नहीं पिघलेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। वर्तमान इंटर ग्लेशियर काल है। दो हिमयुग के बीच इंटर ग्लेशियर काल आता है। एक युग का समय करोड़ों साल होता है। 25 किमी लंबे गंगोत्री ग्लेशियर के 17 मीटर पीछे खिसकने के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यह स्थिति एक दो वर्ष नहीं वरन कई वर्षो की औसत गति के बाद आयी है, जिसे चिंताजनक नहीं कहा जा सकता है। ग्लेशियर के पीछे खिसकने की गति कभी कम होती है तो कभी अपेक्षाकत ज्यादा होती है। केदारनाथ धाम के पीछे लगभग 7 किमी लंबा चोरवाडी ग्लेशियर 7–8 मीटर पीछे गया है। बांयी ओर से इसके साथ मिल रहे लगभग 9 किमी लंबे कम्पेनियन ग्लेशियर के पिघलने की गति ना के बराबर है। पिछले 35 सालों से ग्लेशियर पर अनुसंधान कार्य कर रहे हिम विज्ञानी डा० दीपक श्रीवास्तव इस बात से पूरी तरह नाइत्तिफाक रखते हैं कि ग्लेशियर के पिघलने से कोई संकट आने वाला है।

जीव व पौधे का अनोखा मेल है यार्सा गम्बो

दैनिक जागरण : अगस्त 24, 2007

तीन से साढ़े चार हजार मीटर की ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में पायी जाने वाली इस कीड़ा जड़ी का वैज्ञानिक नाम कार्डइसिपस सिनेसिइस है। तिब्बत में इसे यार्सा गम्बो के नाम से जाना जाता है। जीव और पौधे के अनोखे मेल इस कीड़ा–जड़ी में, कार्डइसिपस सिनेसिइस पौधे का जन्म हैपीएलम वीरेसिनम जंतु के लार्वा के सिर पर होता है। इस जड़ी की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि यार्सा गम्बो बर्फ में रहने वाले कीड़े का परिवर्तित रूप है। यह कीड़ा बर्फ पिघलने के बाद जमीन के नीचे चला जाता है और कुछ समय बाद इस कीड़े के सिर पर लगभग चार इंच पत्तीनुमा घास निकल आती है। तिब्बत और चीन की देसी चिकित्सा पद्धति में यार्सा गम्बो का काफी समय से उपयोग होता रहा है। वर्तमान में भारत में रक्षा कषि अनुसंधान इकाई इस पर शोध कर रही है। प्रारम्भिक चरणों में इसके श्शक्तिवर्द्धक होने की बात साबित हो चुकी है।

सेब उद्यान की तरह होगा हर्बल गार्डन का विकास

दैनिक जागरण : नवम्बर 4, 2007

हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाली बहुमूल्य जड़ी–बूटियों के संरक्षण व संवर्धन के लिए सेब उद्यान की तर्ज पर चौबटिया में हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है। इस उद्यान में विभिन्न प्रजातियों की दुर्लभ हिमालयी जड़ी–बूटियों का रोपण किया जाएगा। चौबटिया में एक हेक्टेयर भूमि में जल्द ही हाईटेक हर्बल गार्डन की स्थापना की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में पाये जाने वाली एक वर्षीय, बहु वर्षीय जड़ी–बूटियों का रोपण करना है। इसके जरिए जड़ी–बूटियों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी, उपयोगिता आदि आम काश्तकारों तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा जड़ी–बूटियों का बीज पौध उत्पादन, कषकों को प्रशिक्षण आदि का कार्य भी किया जाएगा। इससे काश्तकार को इन जड़ी–बूटियों का सही प्रकार से उत्पादन कर आर्थिक लाभ मिलना संभव हो सकेगा। हर्बल गार्डन में जड़ी–बूटियों पर शोध कार्य भी किए जाएंगे। जिसके अन्तर्गत हिमालयी जड़ी–बूटियों की कषि तकनीक विकसित की जाएगी। इसका सीधा लाभ स्थानीय किसानों को मिलेगा। हर्बल गार्डन का उद्देश्य सेब उद्यान की तरह पर्यटकों को आकर्षित कर पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देना भी है।

चिरायता का अस्तित्व संकट मे

अमर उजाला : नवम्बर 15, 2007

अंधाधुंध दोहन के चलते छह से आठ हजार फिट उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर होने वाली चिरायता नाम की जड़ी बूटी लुप्त होने के कगार पर पहुंच गयी है। बुखार, मलेरिया रोग के निदान, बलवर्धक आदि के काम आने वाली चिरायता नाम की जड़ी बूटी का इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है। यह विशिष्ट औषधि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पायी जाती है। लेकिन इस बीच इसके अंधाधुंध दोहन से यह जंगलों से गायब होने लगा है। हिमालयी क्षेत्र में वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर जड़ी बूटियों के तस्कर इस वन संपदा को लूट रहे हैं। इस कारण इसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग गया है।

अल्मोड़ा में खुलेगा पक्षी प्रजनन केंद्र

अमर उजाला : नवम्बर 22, 2007

हिमालयी इलाके में चार हजार से 10 हजार फीट तक की ऊंचाई में पाया जाने वाला खूबसूरत पक्षी चीड़ फीजेंड लुप्त होने के कगार पर है। इस प्रजाति को बचाने के लिए अब इसका प्रजनन केंद्र खोलने का फैसला हुआ है। अनुकूल जलवायु देखते हुए अल्मोड़ा में यह केंद्र स्थापित किया जाना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसे मंजूरी दे दी है। उत्तराखण्ड में चीड़ फीजेंड का यह पहला प्रजनन केंद्र होगा। चीड़ फीजेंड (कैटरिअस वालिची) हिमालयी क्षेत्र में चार हजार से 10 हजार फीट तक की ऊंचाई पर जंगलों में पाया जाता है। इस पक्षी की तादाद लगातार घट रही है। इनके संवर्धन के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने अल्मोड़ा में प्रजनन केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। इस सिलसिले में अल्मोड़ा के प्रभागीय वनाधिकारी ए०के० त्रिपाठी दो अन्य वन अधिकारियों के साथ हिमाचल प्रदेश के चैल में स्थित प्रजनन केंद्र का अध्ययन करके लौट आए हैं।

अल्मोड़ा मग विहार के एक भाग में प्रजनन केंद्र खोला जाएगा व प्रजनन केंद्र का प्रारूप जल्द ही केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को भेजा जाएगा। हिमाचल प्रदेश से चीड़ फीजेंट के जोड़े लाकर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। प्रजनन केंद्र में उत्पन्न होने वाले चीड़ फीजेंट को वनों में छोड़ा जाएगा, ताकि इस लुप्त प्रायः पक्षी का अस्तित्व बना रह सके।

लद्दाख में अठखेलियां करता था समंदर

अमर उजाला : नवम्बर 22, 2007

एडवेंचर के शौकीनों की पसंद लद्दाख में जहां बर्फ का साम्राज्य है, वहां कभी सागर लहराता था। वाडिया हिमालयन भू–विज्ञान संस्थान देहरादून और बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के संयुक्त अध्ययन में यह साबित हुआ है। यहां 33 से 45 मिलियन साल पहले की अवधि के पाम ट्री के फासिल्स मिले हैं। तटीय इलाकों की तरह ये पाम ट्री यहां की खूबसूरती बढ़ाते थे। सात साल से ज्यादा समयावधि के अध्ययन में सामने आया कि आज बर्फीले रेगिस्तान में तब्दील हो चुका लद्दाख तब आज जितनी ऊंचाई यानी, समुद्र तल से 5000 मीटर पर नहीं था। 'स्ट्रक्चरल डिफॉरमेशन ऑफ इंटीरियर अर्थ' प्रोजेक्ट के तहत जम्मू–कश्मीर में वैज्ञानिक दल को पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सोकर के निकट प्लांट फॉसिल्स (पौधों के जीवाश्म) का सेट मिला। यही निष्कर्ष का आधार बना। जमीनी रहस्य उजागर करने के लिए शुरू हुए प्रोजेक्ट में शामिल बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी इंस्टीटयूट के पांच वैज्ञानिकों की टीम का नेतत्व वाडिया हिमालयन भू–विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा० एस०के० पाल ने किया। डा० पॉल के मुताबिक पाम ट्री की उपस्थिति साबित करती है कि 'मिडिल लेट ई–ओशीन पीरियड' में वाकई पाम उस क्षेत्र में था। प्रोजेक्ट के तहत जमीन के भीतरी रहस्य जाने जा रहे हैं। अन्य विदेशी वैज्ञानिक भी नए तथ्यों के सामने आने के बाद प्रोजेक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं। लिहाजा, काफी रहस्यों से परदा उठ सकता हैं।

खटाई में पड़ी बांध बनाने की योजना

अमर उजाला : नवम्बर 26, 2007

कोसी नदी में बर्शिमी नामक स्थान पर बांध बनाने को सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे के लिएश्शासन को 97 लाख रूपये का प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन पांच माह बाद भी इसे स्वीकति नहीं मिल सकी है। इससे बांध बनाने का काम अधर में लटका हुआ है। उल्लेखनीय है कि नगर तथा आसपास के क्षेत्रों की पेयजल समस्या के मद्देनजर कोसी नदी में पिछले काफी समय से बांध बनाने की मांग की जा रही है। इससे जहां अल्मोड़ा का पर्यटन की दष्टि से विकास होता वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलते और मछली पालन को भी बढ़ावा मिलता। बांध से बिजली उत्पादन भी किया जा सकता है। प्रदेश के पेयजल मंत्री भी पूर्व में प्रस्तावित बांध स्थल बर्शिमी का निरीक्षण कर चुके हैं। उन्होंने विभाग को इसकी कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए थे। सिंचाई विभाग ने बांध के सर्वे के लिए 97 लाख का प्रस्ताव बनाकर शासन को पांच माह पूर्व भेज दिया है। जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। सर्वे के तहत बर्शिमी से प्रस्तावित डूब क्षेत्र मटेला तक का भूगर्भीय सर्वेक्षण, सुरंग खोदना, राक की जांच, बांध स्थल तक रास्ता निर्माण, स्टाफ के रहने के लिए भवन बनाना आदि कार्य किए जाएंगे। बांध की ऊंचाई 60 मीटर होने

पर यहां विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता ने बताया कि विभाग द्वारा बर्शिमी में प्रस्तावित बांध क्षेत्र का अक्टूबर 2006 में भारत सरकार के भूगर्भीय वैज्ञानिकों से सर्वेक्षण कराया गया था। इस स्थल को वैज्ञानिकों ने बांध के लिए उपयुक्त बताया है।

मोनाल व कस्तूरा पंहुचे मध्य हिमालयी भूभाग में

दैनिक जागरण : दिसम्बर 7, 2007

प्रदेश के राजकीय पशु कस्तूरा और राजकीय पक्षी मोनाल भारी हिमपात के चलते उच्च हिमालयी भूभाग से मध्य हिमालय की ओर रूख कर चुके हैं। शीतकाल मध्य हिमालय में बिताने के बाद दोनों अपने पसंदीदा स्थल उच्च हिमालय रवाना होंगे। उत्तराखण्ड के राजकीय पशु और पक्षी कस्तूरा और मोनाल उच्च हिमालयी जंतु हैं। हिमरेखा के निकट रहने वाले इन दोनों को शीतकाल में मध्य हिमालय की 10 हजार फीट ऊंचाई पर चोटियों तक आना पड़ता है। दिसम्बर से लेकर मध्य मार्च तक का समय दोनों मध्य हिमालय में ही गुजारते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिमपात देर से होने के कारण मोनाल और कस्तूरा देर से मध्य हिमालय की ओर आते थे। इस बार दिसम्बर की शुरूआत में ही उच्च और मध्य हिमालय की ऊंची चोटियों पर भारी हिमपात होने के कारण इन दुर्लभ पशु–पक्षियों को दिसम्बर के शुरू में ही नीचे आना पड़ा है। कस्तूरा और मोनाल मुनस्यारी के मल्ला जोहरी और धारचूला के दारमा, ब्यास घाटियों में पाये जाते हैं। जहां पर बर्फ गिर कर जमती है उसी के आसपास दोनों डेरा डालते हैं। जानकारों के अनुसार दोनों का आव्रजन काल उनके जीवन के लिए खतरे का समय होता है। हिमालयी मोर कहा जाने वाला मोनाल अपने खूबसूरत पंखों और कस्तूरा नाभि में कस्तूरी के लिए प्रसिद्ध है। प्रकति चक्र के अनुसार इन दोनों को साल में दो बार नीचे आना जाना पड़ता है। इसी दौरान ये शिकारियों के निशाने पर रहते हैं।

तीन पत्तियां खाओ, शुगर फुर्र

दैनिक जागरण : दिसम्बर 9, 2007

गोविंद बल्लभ पंत कषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के वैज्ञानिकों की कवायद सफल रही तो आने वाले दिनों में मधुमेह रोगियों को अंग्रेजी दवाओं और इंसुलिन के झंझट से मुक्ति मिल सकेगी। विकल्प के रूप में ऐसे पौधे पर शोध शुरू हुआ है जो डायबिटिक मरीजों के लिए कारगर है। पौधे की तीन पत्तियों का रोजाना सेवन करने से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पौधे को नाम दिया गया है ''इंसुलिन प्लांट''। शाकीय कुल का यह पौधा दक्षिण भारत के गरम और नम स्थानों में पाया जाता है। पुदीने की तरह चिर हरित पौधे को वहां की जनजातियां शुगर रोग से मुक्ति के लिए बरसों से इस्तेमाल कर रही हैं। बुखार के बाद हुई कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसकी जड़ों को टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका फूल पीला आता है। गरम जलवायु के इस पौधे को फरवरी–मार्च में रोपा जा सकता है।

शीतकाल में फिर संकट में आई गोल्डन महाशीर

विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुकी महाशीर मछली एक बार फिर शीतकाल शुरू होते ही संकट में आ गई है। इसके संकटग्रस्त होने का मुख्य कारण जाड़ों में बर्फीले पानी से बचने के लिये बड़ी नदियों से छोटी

दैनिक जागरण : दिसम्बर 10, 2007

नदियों की तरफ रूख करना है। कम जल स्तर की ओर आने वाली महाशीर मछलियों में से 95 प्रतिशत मछलियों का अवैध शिकार हो जाता है जबकि शेष पोचिंग के कारण मर जाती हैं। 'कोल्ड वाटर फिशेज' की श्रेणी में आने वाली गोल्डन महाशीर (टारपिट्टूटोरा) मुख्य रूप से उत्तराखण्ड की नदियों में पाई जाती है। जिनमें पिथौरागढ़ जनपद की काली नदी मुख्य है। मछली पर संकट का मुख्य कारण डायनामाइट विस्फोट से अवैध शिकार, डैम निर्माण, तथा छोटी नदियों में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग प्रमुख है। इसके अतिरिक्त शीतकाल में गर्म स्त्रोतों की ओर जाने की प्रवति ने भी महाशीर को खतरे में डाल दिया है। पांच से बीस किलो वजनी महाशीर मछली शीतकाल शुरू होते ही गर्म पानी वाली नदियों की ओर रूख करने लगती हैं। इन नदियों की ओर आना ही इस मछली के लिये संकट का कारण बन जाता है। कम जल स्तर की नदियों में पहुंचते ही यह शिकारियों का निशाना बन जाती हैं। इन तमाम कारणों से महाशीर प्रजाति की कई मछलियां विलुप्त हो चुकी हैं।

उगते ही बिक जाएंगी उत्तराखण्ड की जड़ियां

दैनिक जागरण : दिसम्बर 14, 2007

जड़ी–बूटी प्रदेश के नाम से प्रचारित उत्तराखण्ड में प्राकतिक रूप से मिलने वाली जड़ी–बूटियों का भंडार मौजूद है। इनका दोहन पहले से ही औषधीय उत्पादों के लिए किया जा रहा है, पर यह कम ही लोग जानते हैं कि यहां की जमीन और आबोहवा कई देशी व विदेशी प्रजातियों की जड़ी–बूटियों की खेती के लिए मुफीद है। इसे ध्यान में रखते हुए सेंटर फार एरोमेटिक प्लांट (कैप) सेलाकुई की एक महत्वाकांक्षी योजना अंतिम चरण में है। इस योजना के तहत किसानों को जड़ी–बूटियों की खेती के लिए बीज, प्रंसस्करण केंद्र, ग्रेडिंग प्रयोगशाला और विपणन की सुविधा एक ही छत के नीचे मौजूद रहेगी। प्रसंस्करण यूनिट लगाने के लिए कैप ने अमेरिकी तकनीक पर आधारित सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन (एससीएफई) यूनिट के लिए केंद्रीय कामर्स मंत्रलय से लगभग तीन करोड़ रूपए की सहायता प्राप्त करने में सफलता पा ली है। अगले वर्ष तक शुरू होने वाली इस यूनिट को सेलाकुई में स्थापित किया जाएगा। अपनी तरह की इस अत्याधुनिक तकनीक की सहायता से शत–प्रतिशत शुद्धता से जड़ी बूटियों का प्रसंस्करण कर औषधि तेल प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा कैप की विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रसंस्कारित तेल की ग्रेडिंग भी की जाएगी। दूसरी समस्या विपणन के लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तैयार तेल को खरीदने के लिए इंडिया ग्लाइकोल लिमिटेड (आईजीएल) के साथ समझौता भी किया गया है। एससीएफई तकनीक व विपणन के लिए आईजीएल से लगभग 32 करोड़ रूपए का समझौता किया गया है। उत्पादित तेल सीधा आईजीएल को चला जाएगा। लिहाजा किसान को केवल जड़ी बूटियों की खेती करनी है। सचिव उद्यान ने बताया कि अमेरिकी तकनीक पर आधारित प्रसंस्करण केंद्र अगले वर्ष के अंतिम सप्ताह तक काम शुरू कर देगा। कैप के माध्यम से किसानों से एक वर्ष में 80 टन अर्टीमीशिया, 50 टन स्टीविया व अन्य जड़ी बूटियों का उत्पादन कराया जा रहा है। स्थापित किए जा रहे केंद्र ने किसानों की

इस समस्या का समाधान तो किया ही है ग्रेडिंग व विपणन की समस्या भी दूर कर दी है। इसके अलावा सगंध पौधों के प्रसंस्करण के लिए पूरे राज्य में लगभग 27 आसवन केंद्र बनाए जा चुके हैं। जड़ी–बूटी के लिए फिलहाल कोई केंद्र नहीं था।

हाथियों के मूवमेंट का तैयार होगा मानचित्र

दैनिक जागरण : दिसम्बर 17, 2007

वन्य जीव वैज्ञानिक की मेहनत सफल हुई तो आने वाले दिनों में हाथियों के मूवमेंट की जानकारी लगाकर उनके महत्वपूर्ण गलियारे को जानने के बाद उसका नक्शा तैयार किया जा सकेगा। नक्शा हाथियों के चलने की दूरी, किन क्षेत्रों में उनका प्रवास और कौन–कौन से मौसम में वह कहां भ्रमण कर रहे हैं, यह सब जानना आसान हो जायेगा। फिलहाल राजाजी के चीला और हरिद्वार रेंज में इस कवायद को वन्य जीव वैज्ञानिक शुरू करने जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक की जीपीएस के द्वारा यह सब संभव होगा। हाथियों के मूवमेंट को लेकर देश के कई वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं लेकिन उनके मूवमेंट की सही स्थिति की जानकारी के लिए अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। हाथियों की जहां साइटिंग हो रही है, उसे ही मूवमेंट बताया जा रहा है। जिससे हाथी के गलियारों का अध्ययन काफी हद तक सटीक तरीके से जंगलात के अधिकारी और वनकर्मी नहीं कर पा रहे हैं। अब वन्य जीव वैज्ञानिक राजाजी के चीला रेंज और हरिद्वार रेंज में आधुनिक तकनीक से युक्त जीपीएस से हाथियों के मूवमेंट को लेने की कवायद में जुटें है। जीपीएस की इस तकनीक के तहत पहली बार हाथियों के भ्रमण क्षेत्र के बारे में सही जानकारी जुटाई जाएगी। जब यह जानकारी पूरी हो जाएगी तो इसका एक नक्शा तैयार होगा, जिसमें हाथियों के मूवमेंट को दर्शाया जाएगा। इस विधि से एक फायदा यह भी मिलने वाला है कि हाथियों का मूवमेंट किन–किन मौसम में किस ओर होता है, यह जानना आसान होगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी पता चलेगी उसमें हाथियों के मूवमेंट का किलोमीटर जाना जा सकता है। यदि वह नदी, जंगल या कहीं और प्रवास कर रहे हैं तो वह भी जाना जा सकेगा। तकनीक से रात्रि भ्रमण की जानकारी लेना भी अब आसान होगा। वन्य जीव वैज्ञानिक डा० रितेश जोशी ने बताया कि हालांकि यह बेहद कठिन और मेहनत से भरा काम है, बावजूद चीला रेंज में इस कार्य को शुरू किया जा रहा है। उन्होने बताया कि जब हाथियों के मूवमेंट की ठोस जानकारी लग जाएगी तो रेंज के नक्शे पर इसे रख दिया जाएगा। जो एलीफेंट मूवमेंट के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि हाथियों की समुद्र तल से ऊंचाई मापी जा सकेगी। यानि इससे यह भी पता चलेगा कि किस समय हाथी कितनी ऊंचाई से आवागमन कर रहे हैं।

वर्ल्ड हेरिटेज में चमकेगा सबसे बुजुर्ग चिनार

अमर उजाला : दिसम्बर 27, 2007

मुगलकाल के राजशाही पेड़ चिनार की चमक रियासत में आज भी बरकरार है। इस चमक को दुनियां के सामने और बढ़ाने जा रहा है एक सबसे बुजुर्ग चिनार। कश्मीर के बड़गाम जिले के छतरगाम में मौजूद इस चिनार को दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना होने का दावा संयुक्त राष्ट्र के सामने होने जा रहा है। मकसद वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको शामिल

कराने का है। कश्मीर की पहचान बन गए चिनार को सैकड़ों साल पहले मुगल शासकों ने घाटी में रोपा था। तबसे चिनार के दरख्त, पत्तियां और इसकी छांव ने अपनी पहचान कायम रखी है। सात सौ साल पुराने इस पेड़ के तने की परिधि 31.85 मीटर तथा पेड़ की ऊंचाई 14.78 मीटर है। रियासत के प्रसिद्ध पर्यावरण विद् मुहम्मद सुलतान वादू अपनी किताब 'द ट्री ऑफ आवर हेरिटेज' में सालों पहले ही इसके दुनिया का सबसे पुराना चिनार होने का दावा कर चुके हैं। चिनार की प्रमाणिक उम्र के लिए 'कार्बन डेटिंग' तकनीक का सहारा लिया जाएगा। इस तकनीक में चिनार के पौधे का थोड़ा हिस्सा लेकर प्रयोगशाला में कार्बन क्षरण की दर देखकर उम्र का पता चल जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की मदद ली जाएगी। रियासत में एक तरफ सात शतक पुराना राजशाही पौधा अपनी नई पहचान बनाने जा रहा है वहीं मुगलकाल में कश्मीर में लगे चिनार के पेड़ पिछले तीन दशक में कम हो रहे हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार तीस हजार से ज्यादा पेड़ काट दिए गए हैं। सन् 1976 में राज्य में करीब 42000 चिनार के पेड़ थे, जो अब घटकर मात्र 16000 रह गए हैं। चिनार विकास प्राधिकरण घाटी में चिनार के पौधे मुफ्त में बांट रहा है।